अगले दशक में तेज विकास की जमीन तैयार : आरबीआइ

केंद्रीय बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा- भारतीय इकोनमी को मिलेगा जनसांख्यिकीय और प्रतिस्पर्धी होने का लाभ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत अगले एक दशक तक तेज आर्थिक विकास दर हासिल करने की स्थिति है। बैंकों और कारपोरेट जगत की बेहद मजबूत स्थिति, सरकारी खर्चे की गुणवत्ता को सुधारने की कोशिशें, विवेकपूर्ण मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों के साथ ही महंगाई में नरमी की वजह से मजबूत इकोनमी की जमीन तैयार हो चुकी है। ऐसे में श्रम में योगदान करने वाले उम्र वर्ग के लोगों की बड़ी आबादी और प्रतिस्पर्द्धी होने का फायदा उठाते हुए भारत एक दशक तक तेज आर्थिक विकास की अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। यह बात गुरुवार को जारी हुई आरबीआइ की सालाना रिपोर्ट 2023-24 में कही गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान बेहद अस्थिर वैश्विक हालात में भारत की इकोनमी ने स्थिरता व मजबूती दिखाई है। रिपोर्ट में भारत ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान वैश्विक अस्थिरता के बावजूद जिस तरह से लगातार सात प्रतिशत से ज्यादा की तेज विकास दर हासिल की है, उसको एक बड़ा संकेत माना गया है। भारत पिछले तीन वर्षों से लगातार सात प्रतिशत या इससे ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ा है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2025 और वर्ष 2026 में भी भारत की विकास दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रहेगी।

रिपोर्ट में महंगाई की स्थिति को लेकर भी कोई खास चिंताजनक बात नहीं कही गई है। हालांकि आने वाले वर्षों में विकास की संभावनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का तेजी से इस्तेमाल सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। बिगड़ता मौसम भी विकास की संभावनाओं को धीमा कर सकता है। हालांकि यह समस्याएं मध्यावधि में ही रहेंगी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर काफी है जो वैश्विक संकटों से घरेलू इकोनमी को बचा सकता है। वित्तीय सेक्टर काफी मजबूत दिख रहा है और इसे ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए आरबीआइ मुस्तैद है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बदलता मौसम ही इकोनमी के लिए बड़ी चिंता
- जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज का अनुपात 22.4% से घटकर 18.7% हुआ

बिना दावे वाली राशि 26 प्रतिशत बढ़कर 78,213 करोड़ रुपये

मार्च, 2024 के अंत तक बैंकों के पास बिना दावे वाली राशि 26 प्रतिशत बढ़कर 78,213 करोड़ रुपये हो गई है। मार्च, 2023 के अंत तक निवेशक जागरूकता कोष में 62,225 करोड़ रुपये की राशि थी। 10 या उससे अधिक वर्षों से बैंक में पड़ी ऐसी राशि, जिस पर किसी तरह का दावा नहीं किया जाता है, उसे निवेशक जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर देते हैं।

चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत रहेगी विकास दर

चालू वित्त वर्ष में कृषि व ग्रामीण इकोनमी की स्थिति ठीक दिख रही है। गरीब कल्याण अन्न योजना के पांच वर्षों तक के लिए लागू होने से खाद्य सुरक्षा की स्थिति मजबूत हुई है। रोजगार सृजन भी इस साल बेहतर होगा क्योंकि सरकार की पीएलआइ स्कीम का असर दिखना शुरू होगा। इन स्कीमों से श्रम की मांग बढ़ेगी और घरेलू मांग भी बेहतर होगी। इस आधार पर ही चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत सात प्रतिशत की विकास दर हासिल करने की बात कही गई है। महंगाई को लेकर रिपोर्ट कहती है कि पिछले वित्त वर्ष यह औसतन 5.4 प्रतिशत रही है जो चालू वित्त वर्ष में और कम होगी। वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रह सकती है। आरबीआइ इसे चार प्रतिशत के स्तर पर लाने की कोशिश में है।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले बढ़े, पर राशि 47 प्रतिशत घटी

प्रेट्र के अनुसार, बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले बीते वित्त वर्ष (2023-24) में बढ़कर 36,075 हो गए। एक साल पहले इनकी संख्या 13,564 थी। हालांकि, इस दौरान धोखाधड़ी वाली राशि 46.7 प्रतिशत घटकर 13,930 करोड़ रुपये रही। एक साल पहले यह राशि 26,127 करोड़ रुपये थी। आरबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन साल में धोखाधड़ी के मामलों के आकलन से संकेत मिलता है कि जहां निजी क्षेत्र के बैंकों ने सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के मामलों की सूचना दी, वहीं धोखधड़ी में शामिल राशि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान पहले की तरह सबसे ज्यादा रहा। छोटी राशि के कार्ड/इंटरनेट धोखाधड़ी के मामले में निजी क्षेत्र के बैंकों में सबसे ज्यादा मामले आए। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी मुख्य रूप से कर्ज श्रेणी में रही। रिपोर्ट में आरबीआइ ने कहा कि वह भारत से बाहर भी रुपया खाता खोलने की अनुमति देगा। रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्रा बनाने की रणनीतिक योजना के तहत यह अनुमति दी जाएगी।

निवेशकों ने 27,031 करोड़ रुपये के सावरेन गोल्ड बांड खरीदे

पिछले वित्त वर्ष में निवेशकों ने 27,031 करोड़ रुपये के सावरेन गोल्ड बांड खरीदे। यह राशि अधिक रिटर्न और कर लाभ से जुड़ी स्कीमों में निवेश की गई राशि से चार गुना ज्यादा है। 2022-23 में, 12.26 टन सोने का प्रतिनिधित्व करने वाले सावरेन गोल्ड बांड 6,551 करोड़ रुपये में खरीदे गए थे। नवंबर, 2015 में एसजीबी की शुरुआत से अब तक 72,274 करोड़ रुपये (146.96 टन सोना) जुटाए गए हैं।